उपद्रव व तनाव का व्यापार और परीक्षाओं पर दिखा असर

सिहोरा काण्ड: 60 से अधिक गिरफ्तारियां

हरिभूमि न्यूज जबलपुर।

गुरुवार रात भड़के साम्प्रदायिक तनाव के बाद सिहोरा को पूरी तरह शांत करने के लिए प्रशासन और पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लगातार तीसरे दिन भी कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात रहा। शुक्रवार देर रात एक बार फिर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया और 60 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों को माढ़ोताल थाने में ही रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ जारी है। जिसका असर था की शनिवार सुबह तक सिहोरा पटरी पर लौट आया। बाजार खुलने लगे और सड़क पर चहल पहल नजर आई। हालांकी शनिवार को हुई 5-8 वीं बोर्ड परीक्षाओं में बीते दिनों हुई हिंसा का असर साफ देखने मिला, सिहोरा अंतर्गत आने वाले स्कूलों में हुई परीक्षा में करीब 450 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। प्रशासन का दावा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन लोगों में दहशत का माहौल अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा असर स्थानीय व्यापार पर पड़ा है। दो दिन पहले तक निर्भय होकर दुकानें खोलने वाले व्यापारी अब सहमे हुए नजर आ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार रात करीब साढ़े नौ बजे दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने तनाव का रूप ले लिया था। हालात बमुश्किल काबू में आए थे। कलेक्टर और एसपी को दो बार मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी थी। एसपी सम्पत उपाध्याय ने दोहराया कि किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचा है और पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

जनजीवन पटरी पर लौटने लगा

घटना के तीसरे दिन शनिवार सुबह से जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य होता दिखाई दिया। लोग अपने रोजमर्रा के कामों के लिए घरों से निकलने लगे। आधे से अधिक बाजार खुल गए, हालांकि ग्राहक संख्या अभी भी कम है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार कई थानों की पुलिस, सीएसपी और टीआई स्तर के अधिकारी पूरे सिहोरा कस्बे में तैनात हैं। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।

दहशत के साए में हुईं परीक्षाएं

तनाव के बीच कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी आयोजित हुईं। शासकीय कन्या शाला और सीएम राइज स्कूल में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। मुख्य मार्ग बस स्टैंड से होकर गुजरता है, जहां विवाद और हंगामा हुआ था। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों को कई किलोमीटर बाइपास मार्ग से घुमाकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना पड़ा।

परीक्षा में 450 बच्चे अनुपस्थित

छात्रों ने दहशत के माहौल में परीक्षा दी। कुल 30 परीक्षा केंद्रों पर 6371 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 5886 छात्रों ने परीक्षा दी, जबकि 450 से अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। कक्षा 5 के हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की अंग्रेजी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की हिंदी परीक्षा आयोजित हुई।

व्यापार पर पड़ा सबसे ज्यादा असर

स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि दो दिन की बंदी और भय के कारण कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही हालात पूरी तरह सामान्य होंगे। फिलहाल सिहोरा में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस और प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में फ्लैग मार्च

कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के नेतृत्व में शुक्रवार देर रात निकाले गए फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, एएसपी जोन-3 सूर्यकांत शर्मा, यातायात एएसपी अंजना तिवारी, एसडीओपी सिहोरा, पाटन सहित जिले भर के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे। फ्लैग मार्च सिहोरा के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरा। अधिकारियों ने आम नागरिकों से शांति और एकता बनाए रखने की अपील की तथा अफवाहों से दूर रहने को कहा।

हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा

महिला प्राध्यापक की शिकायत पर की गई जांच की रिपोर्ट उसे क्यों नहीं दी

हरिभूमि जबलपुर।

मप्र हाईकोर्ट ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा है कि महिला प्राध्यापक की शिकायत पर की गई जांच की रिपोर्ट उसे क्यों नहीं दी गई। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने जेएनकेविवि के रजिस्ट्रार, हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन, कृषि विज्ञान केन्द्र के वरिष्ठ साइंटिस्ट, एसपी छिंदवाड़ा व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। छिंदवाड़ा निवासी पीड़िता की ओर से अधिवक्ता मनीष वर्मा एवं विनोद सिसोदिया ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर कॉलेज छिंदवाड़ा के डीन डॉ आरसी शर्मा ने पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न किया था। इस मामले में आईजी, एसपी सहित कई मंचों पर शिकायत की गई। राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग में भी शिकायत की गई। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम के तहत कृषि विश्वविद्यालय ने एक कमेटी बना कर जांच कराई गई। दलील दी गई कि उक्त अधिनियम के तहत कमेटी में महिला का होना जरूरी है, जबकि उक्त समिति में पुरुष अधिकारी को हेड बनाया गया था। कमेटी ने 8 अक्टूबर 2025 को जांच की थी, लेकिन अभी तक पीड़िता को उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

हाईकोर्ट की पहल : अवकाश के दिन न्यायपालिका के कर्मचारियों के निपटाए विवाद

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की पहल पर अवकाश के दिन जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के सेवा-संबंधी विवादों को आपसी सहमति से निपटाने के उद्देश्य से मध्यस्थता प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया है। प्रशासनिक न्यायमूर्ति विवेक रूसिया तथा जस्टिस विवेक अग्रवाल के निर्देशन में शनिवार को उच्च न्यायालय परिसर के साउथ हॉल में एक विशेष मध्यस्थता सत्र का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सत्र में कुल 43 प्रकरण प्रस्तुत किए गए।।जिनमें से 25 मामलों का संवाद एवं सहमति के आधार पर तत्काल निराकरण किया गया। इस दौरान स्थानीय के अलावा विभिन्न जिलों में पदस्थ कर्मचारियों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रभावी रूप से भाग लिया। वर्ष 2005 एवं 2010 से लंबित प्रकरणों का भी सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस दौरान रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह सहित अन्य रजिस्ट्रार उपस्थित रहे। साथ ही हाई कोर्ट पैनल के वरिष्ठ अधिवक्तागण आदित्य अधिकारी, अनूप नायर, बीएन मिश्रा,अमृत रूपराह, आकाश चौधरी, सिद्वार्थ सेठ, केएन फखरुद्दीन, संदीप के शुक्ला, राजेन्द्र सेन, पराग तिवारी, मिहिर अग्रवाल, संपत कुशवाहा, श्रीमती नीलम गोयल, अभिषेक अर्जारिया, अंजली पटेल, विवेकानंद अवस्थी एवं राहुल चौबे का सक्रिय सहयोग रहा।

स्वच्छता ही सेवा' : निगमायुक्त सड़कों पर उतरे, सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण

जबलपुर। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से जबलपुर नगर निगम के निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने आज सुबह विभिन्न क्षेत्रों का सघन दौरा कर सफाई व्यवस्थाओं का जमीनी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने रामपुर एवं गोरखपुर के रिहायशी और व्यावसायिक इलाकों में कचरा संग्रहण व्यवस्था का जायजा लिया। मेडिकल क्षेत्र में अस्पतालों के आसपास चल रहे विशेष सफाई अभियान की समीक्षा की। साथ ही अंधमुक बायपास एवं धनवंतरी नगर में मुख्य सड़कों और डिवाइडरों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वच्छता के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कचरा वाहनों की समय पर उपस्थिति, सार्वजनिक डस्टबिनों की नियमित सफाई एवं खाली कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को भी जागरूक किया जाए, ताकि वे कचरा सड़कों पर न फेंककर सीधे कचरा गाड़ियों में ही डालें। इस दौरान अधीक्षण यंत्री कमलेश श्रीवास्तव, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक संतोष महोर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक हरि ओम शर्मा को निर्देश

अदालत में हाजिर होकर बताएं झूठा हलफनामा क्यों पेश किया

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक हरि ओम शर्मा को निर्देश दिए हैं कि वे व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर यह स्पष्टीकरण दें कि उन्होंने अदालत में झूठा हलफनामा क्यों पेश किया। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने महाप्रबंधक को 23 फरवरी को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। यह मामला भोपाल मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 के समीप चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न अवरोध एवं बैरिकेडिंग से संबंधित है।

भोपाल निवासी श्रीनिवास अग्रवाल व अन्य की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मेट्रो प्रबंधन ने फेंसिंग और बैरिकेडिंग पूरी तरह से नहीं हटाई है। इससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। इस पर मेट्रो रेल प्रशासन की ओर से हलफनामे में कहा गया कि बैरिकेडिंग हटा दी गई है। इस पर हाईकोर्ट ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी थी। कलेक्टर भोपाल द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण के आधार पर रिपोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं को मात्र लगभग 3।75 फीट का संकरा मार्ग उपलब्ध कराया गया है, जो व्यवहारिक उपयोग हेतु पर्याप्त नहीं है। यह भी बताया गया कि तीनों ओर की बैरिकेडिंग हटाई नहीं गई है, जबकि महाप्रबंधक द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत शपथपत्र में यह उल्लेख किया गया था कि बैरिकेडिंग पूर्णतः हटा दी गई है।

राहुल के पुतले को लेकर गहमागहमी

पुलिस छावनी में तब्दील रहा बलदेवबाग इलाका

जबलपुर। शनिवार को दोपहर के वक्त बलदेवबाग से आगाचौक तक उस समय सनसनी फैल गई, जब पुलिस ने मार्ग को चारों तरफ से घेर लिया और रास्ते सील कर दिये। एसडीएम सहित तहसीलदार, सीएसपी व तीन थानों के प्रभारी और भारी पुलिस बल तैनात था। इस बीच काफी गहमागहमी का माहौल बना रहा। दरअसल यहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा दिल्ली में एआई समिट के दौरान युवक कांग्रेस द्वारा अर्धनग्न होकर किये गये प्रदर्शन के खिलाफ राहुल गांधी का पुतला जलाने की घोषणा की गई थी। चूंकि बलदेवबाग में कांग्रेस कार्यालय है लिहाजा मामला राजनीतिक संवेदनशीलता से जुड़ गया। पूर्व में कांग्रेस कार्यालय में हुई तोड़फोड़ की घटना को ध्यान में रखकर प्रशासन ने पूरी सतर्कता रखी। क्षेत्र को पुलिस छावनी में बदल दिया। शाम 5 बजे कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुये। दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। पुलिस के पहरे में बलदेवबाग चौराहे पर युवा मोर्चा ने राहुल गांधी का पुतला जलाया। भाजपा के तरफ से भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेस सोनकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह ठाकुर, अंकित पाठक, रौनक अग्रवाल आदि शामिल थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से अमरीष मिश्रा, अनुराग गढ़ावाल, पार्षद आयोध्या तिवारी, संतोष पंडा, हर्षित यादव, वरिष्ठ नेता रीतेश अग्रवाल सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जस्टिस एनके मोदी निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

जबलपुर। आगामी स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्यप्रदेश के चुनाव में जस्टिस एनके मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस संबंध में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई को 30 अप्रैल 2026 तक स्टेट बार के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। ये चुनाव जस्टिस आरएस झा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की निगरानी में संपन्न होगा।

समय पर टैक्स जमा कर शहर विकास में सहभागी बनने की अपील

नगर निगम का राजस्व वसूली अभियान तेज

जबलपुर। जबलपुर नगर निगम ने राजस्व वसूली अभियान में तेजी ला दी है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शहर के सभी सम्माननीय नागरिकों और करदाताओं से अपील की है कि वे अपने बकाया करों का समय पर भुगतान कर शहर विकास में सहभागी बनें।

महापौर ने समीक्षा बैठक में कहा कि बेहतर सड़कें, स्वच्छ पेयजल, कचरा प्रबंधन और आधुनिक अधोसंरचना के लिए पर्याप्त राजस्व आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से सम्पत्तिकर, जलकर, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुल्क, किराया, लीज एवं अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) शुल्क सहित सभी प्रकार के निगम कर शीघ्र जमा करने का आग्रह किया।

महापौर ने राजस्व वसूली अभियान की समीक्षा करते हुए राजस्व अमले को पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक वसूली का लक्ष्य दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि यह वसूली के लिए उपयुक्त समय है, इसलिए अधिकारी-कर्मचारी घर-घर जाकर करदाताओं से संपर्क करें और बकाया राशि जमा कराएं। बैठक में महापौर ने घोषणा की कि लक्ष्य से अधिक वसूली करने वाले अमले को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कम वसूली करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

1 लाख से अधिक बकायेदारों पर कुर्की की सख्त कार्रवाई

निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने 16 संभागों के 79 वार्डों में चिन्हित एक लाख रुपये से अधिक के बकायेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि संबंधित बकायेदारों से बार-बार संपर्क के बावजूद यदि कर जमा नहीं किया जाता है तो कुर्की की कार्रवाई की जाए और उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशन कराया जाएगा। बैठक में राजस्व प्रभारी एमआईसी सदस्य डॉ। सुभाष तिवारी, सहायक आयुक्त आनंद मिश्रा, राजस्व प्रभारी मयंक चौरसिया सहित सभी संभागीय अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं बाजार निरीक्षक उपस्थित रहे।

46 वाहनों चालकों से 29 हजार जुर्माना वसूला

यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही

जबलपुर। जिला पुलिस बल ने पिछले 24 घंटों के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा वहीं आवागमन में अवरोध पैदा कर रहे। अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही करते हुये 34 पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही की गई। गये। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 46 वाहन चालकों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 29 हजार 600 रूपये समन शुल्क वसूला गया। पिछले 24 घंटे में आदतन अपराध करने वाले 27 आरोपियों के विरूद्ध धारा 129 बी।एन।एस।एस के तहत, तथा वाद विवाद करने वाले 96 व्यक्तियों के विरूद्ध 126/135 (3) बी।एन।एस।एस (107/116 जा।फौ।) के तहत, एवं 5 व्यक्तियो के विरूद्ध धारा 170 बी।एन।एस।एस (151 जा।फौ।) के तहत की गयी है, इसी प्रकार पिछले कई वर्षो से फरार 2 गैरम्यादी, 33 म्यादी वारंटी, को गिरफ्तार किया गया है एवं 72 जमानती वारंट तामील किये गये तथा सार्वजनिक स्थान पर शराब पिलाने वाले व्यक्तियों सहित, अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 22 व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 207 पाव देशी/अंग्रेजी एवं 35 लीटर कच्ची शराब जप्त की गयी तथा 3 व्यक्तियो के विरूद्ध 25 आम्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 3 चाकू जप्त किये।

प्रेम विवाह से नाराज़ पिता ने बेटी पर किया हमला

जबलपुर। गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वंशकार मोहल्ले में देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां प्रेम विवाह से नाराज़ पिता ने अपनी ही बेटी पर बांस छीलने वाली 'बाकी' से हमला कर दिया। घायल युवती ने थाने पहुंचकर मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। गोरखपुर पुलिस थाना से प्राप्त जानकारी अनुसार वंशकार मोहल्ला निवासी आरती वंशकार बांस की टोकरी बनाने का कार्य करती है। उसने करीब एक सप्ताह पूर्व अमित वंशकार से अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया था। विवाह के बाद 18 फरवरी को वह अपने पिता मुकेश वंशकार के घर आई थी। शुक्रवार शाम वह घर पर मौजूद थी, तभी उसके पिता मुकेश वंशकार प्रेम विवाह को लेकर उससे नाराजगी जताने लगे। इसी बात को लेकर उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी। जब आरती ने उन्हें गालियां देने से मना किया तो पिता का गुस्सा बढ़ गया। आरोप है कि इसी दौरान मुकेश वंशकार ने बांस छीलने में उपयोग होने वाली 'बाकी' से उस पर हमला कर दिया। वार से आरती की हाथ की कलाई में चोट आई। घटना के बाद आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। घायल युवती ने साहस दिखाते हुए गोरखपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

दोस्त ने फोन कर पूछा कहां हो आकर मार दी चाकू

जबलपुर। खितौला थाना अंतर्गत बाजार में एक युवक को बदमाश ने पहले फोन किया और बोला आज तुमसे लड़ाई करना तुम कहा हो, उसने कहा बाजार में, इसी बीच आरोपी बाजार पहुंचे और गालीगलौच कर उसके साथ मारपीट की और चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। बताया गया है कि घायल युवक की आरोपी से एक साल पुरानी मित्रता भी है। खितौला पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार सक्री मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय अरविंद चक्रवर्ती की सौरभ कुचबंधिया से लगभग एक साल से मित्रता थी। कल रात 8 बजे सौरभ ने अरविंद को फोन किया और बोला की तुमसे लड़ाई करना है, कहा हो। उसने कहा खितौला बाजार में हैं। इसी बीच सौरभ कुचबंधिया और गुरुकुचबंधियां पहुंचे और गाली गलौच कर मारपीट करने लगे। आकाश बिरहा ने बीच बचाव किया। इस मारपीट में आकाश भी घायल हो गया। चाकू के वार से अरविंद चक्रवर्ती को गंभीर चोट आई। पुलिस ने रिपोर्ट पर धारा 296(ए), 115(2), 109(1), 351(2), 3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

श्रीराम मंदिर खैरी शहपुरा भिटौनी में हुई पांचवे दिन की श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में बोले जगतगुरु नरसिंह देवाचार्य महाराज

भक्ति में विश्वास सर्वोपरि

जबलपुर, शहपुरा। "भक्त का भगवान पर पूर्ण विश्वास अति आवश्यक है, क्योंकि विश्वास रूपी ईंट जितनी मजबूत होगी हमारे संबंधों की दीवार उतनी ही टिकाऊ बन पायेगी। संबंधों की मजबूती के लिए परस्पर विश्वास प्रथम आवश्यकता है। अविश्वास प्रेम को चोट पहुंचाता है, जिससे परस्पर संबंधों की मजबूत दीवारों में भी दरारें आ जाती हैं। विश्वास ही संबंधों को प्रेममय बनाने का आधार है। जब प्रत्येक बात का मूल्यांकन स्वयं के नजरिए से किया जाता है, तो वहाँ अविश्वास उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यह आवश्यक नहीं कि हर बार हमारे मूल्यांकन का दृष्टिकोण सही हो, इसलिए संबंधों की मधुरता के लिए अपने दृष्टिकोण के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं तक पहुँचने का गुण भी हमारे भीतर अवश्य होना चाहिए। संबंध जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं अपितु संबंध निभाना महत्वपूर्ण है। संबंधों का जुड़ना संयोग हो सकता है पर संबंधों को निभाना भी जीवन की एक साधना है। संबंधों की इमारत का निर्माण 'विश्वास रूपी ईंट' से किया जाना श्रेष्ठकर है। श्री राधे कृष्ण ने विश्वास से ही आदर्श स्थापित किया है। ईश्वर पर विश्वास करने से ही भक्त के सभी कष्टों और दुख दर्द दूर हो जाते हैं।" उक्त विचार श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस श्रीराम मंदिर खैरी शहपुरा भिटौनी में पूज्य जगदगुरू नृसिंह पीठाधीश्वर डॉ. स्वामी नृसिंहदेवाचार्य महाराज ने व्यास पीठ से व्यक्त किए।

व्यास पीठ पूजन मुख्य यजमान सुभाष सिंह गौर व कृपाल सिंह गौर, राजेश सिंह गौर, कृष्णपाल सिंह गौर, जयपाल सिंह गौर, अनूपाल सिंह गौर, शैलेन्द्र सिंह गौर, रोहित सिंह गौर, अजय सिंह गौर, डॉ. दीपक सिंह गौर, विक्रम सिंह गौर, आदित्य सिंह गौर, अभिराज सिंह गौर, युवराज सिंह गौर, अमित टेहगुनिया एवं आचार्य रामफल शास्त्री की उपस्थिति में किया गया।

मातृभाषा का सम्मान, अपनी संस्कृति का सम्मान है : प्रो. अरुण शुक्ल

अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर हुआ व्याख्यान एवं शपथ कार्यक्रम

जबलपुर। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना एवं हिंदी विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय महाकोशल स्वशासी महाविद्यालय, जबलपुर के संयुक्त तत्वावधान में आज अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर व्याख्यान एवं शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रो. अरुण शुक्ल, संभागीय नोडल अधिकारी, स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना, जबलपुर संभाग ने कहा कि मातृभाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान, संस्कृति, परंपरा और संवेदनाओं की जीवंत धारा है। हम जिस भाषा में सोचते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, वही हमारी मातृभाषा है। हमारी मातृभाषा हमें समाज और परिवार से जोड़ती है। मातृभाषा का सम्मान, अपनी संस्कृति का सम्मान है।

इस अवसर पर प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों द्वारा शपथ ली गई कि वह अपनी मातृभाषा का सम्मान और नियमित उपयोग करेंगे और दैनिक जीवन में मातृभाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. ए.सी. तिवारी, डॉ. मृत्युजय सिंह, डॉ. शैलप्रभा कोष्टा, डॉ. विभा निगम, डॉ. मीना केलर, डॉ. चित्रा राय, डॉ. रामेश्वर झारिया, डॉ. नीलू रघुवंशी, डॉ. रविश तमन्ना, डॉ. विभा चौधरी, डॉ. मनीषा सक्सेना, डॉ. जागेश्वर प्रजापति, डॉ. मीनाक्षी मेरावी, डॉ. रानु रंगडाले, डॉ. उमा धुर्वे, डॉ. नीलिमा के साथ विद्यार्थी उपस्थित रहे।

होली के पूर्व तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग

बरेला। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के तहसील सचिव शुभ संदेश सिंगोर ने शासन से प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई माह से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई माह से तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते का भुगतान प्रारंभ कर दिया है आठ माह बीत जाने के बाद भी राज्य शासन ने महंगाई भत्ता की घोषणा नहीं की जिससे राज्य कर्मचारियों में भीषण महंगाई के दौर में असंतोष व्याप्त है जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, तहसील अध्यक्ष रजनीश कुमार पाण्डेय, डालचंद पासी, शहजाद द्विवेदी, मुकेश मेहरा, शुभ संदेश सिंगौर, अंशुल साहू, रामदास वरकडे ,निर्मल लोधी,सतीश बड़कडे, बृजेश दीक्षित, सतीश उपाध्याय, आदि ने होली के पूर्व तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते देने की मांग की है।

आदित्य गुरु बने जिला संगठन मंत्री, ब्राह्मण समाज में हर्ष

पाटन। अखंड ब्राह्मण महासभा में पाटन निवासी पंडित आदित्य गुरु को जिला संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्रनाथ शुक्ला एवं राष्ट्रीय महासचिव हीराकांत महाराज द्वारा संस्थापक अध्यक्ष पंडित जगदीश प्रसाद दुबे की अनुशंसा पर की गई। पंडित आदित्य गुरु पाटन के प्रतिष्ठित गुरु परिवार से संबंध रखते हैं। वे पाटन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक स्व. पंडित भगवत प्रसाद गुरु के नाती एवं पूर्व नगर परिषद पाटन अध्यक्ष पंडित संजय गुरु के सुपुत्र हैं। समाज के प्रति उनकी निष्ठा, समर्पण और निस्वार्थ सेवा को देखते हुए संगठन ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी नियुक्ति से नगर एवं आसपास के ब्राह्मण समाज में खुशी का माहौल है। समाजजनों ने इसे युवा नेतृत्व को मजबूती देने वाला कदम बताते हुए आदित्य गुरु को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

19 दिनों से जारी धरनाः भुगतान न मिलने से 315 किसान परेशान

मझौली

क्षेत्र में कथित धान खरीदी धन घोटाले को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार 19वें दिन भी जारी रहा। भारतीय किसान संघ के बैनर तले 3 फरवरी 2026 से शुरू हुआ धरना-अनशन अब उग्र रूप लेता जा रहा है। किसानों का आरोप है कि योजना में वित्तीय अनियमितताओं के कारण उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन अब तक दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसान नेताओं के अनुसार 5 फरवरी को क्षेत्रीय विधायक धरना स्थल पहुंचे थे। 6 फरवरी को विधायक के साथ कलेक्टर की बैठक हुई और आश्वासन दिया गया। इसके बाद जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी प्रमोद मिश्रा ने मझौली पहुंचकर किसानों से चर्चा की और बताया कि 14,905 क्विंटल धान श्री जी वेयरहाउस में कम पाई गई है। जांच के बाद भुगतान का भरोसा दिया गया, पर अब तक समाधान नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि 315 किसानों का भुगतान लंबित है।

इनमें से 174 किसानों का भुगतान जांच के दौरान किए जाने की बात कही जा रही है, जबकि शेष 141 किसानों को न तो भुगतान मिला है और न ही उनका माल लौटाया गया है। इस मुद्दे पर किसान और प्रशासन के बीच दो बार वार्ता भी हुई, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका। धरना स्थल पर किसान लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। किसान संघ मझौली अध्यक्ष बीरेंद्र पटेल ने चेतावनी दी है कि जब तक सभी किसानों को भुगतान नहीं किया जाता और दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बरेला को मिले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पूर्ण तहसील का दर्जा

बरेला। आजादी के 75 साल बाद भी आज भी नगर वासियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पूर्ण तहसील का दर्जा ना मिल पाने से नगर वासियों को छोटे-छोटे कार्यो के लिए शहर की ओर दौड़ लगाना पड़ता है। नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा तो है किंतु अस्पताल में भर्ती की सुविधा ना होकर केवल रिफर केंद्र बन गया है। यहां पर आने वाले मरीजों को केवल सर्दी, खांसी, जुखामऔऱ बुखार की गोलियां मिलती हैं। बड़ी बीमारी होने पर उन्हें जबलपुर रिफर कर दिया जाता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा मिल जाने पर यहां पर जहां एक और बिस्तरों की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां दूसरी ओर स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हो जाएगा। वही नगर में केवल उप तहसील कार्यालय है और इस उप तहसील कार्यालय में केवल लोक सेवा केंद्र हैं और अन्य कोई सुविधाएं नहीं हैं।लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए भी जबलपुर तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं जिसके कारण लोगों को मध्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। नगर को पूर्ण तहसील का दर्जा मिल जाने से लोगों को छोटे- छोटे कार्यों के लिए शहर जाने से निजात मिल जावेगी। नगर वासियों ने क्षेत्रीय विधायक सुशील तिवारी व जिले के प्रभारी मंत्री से नगर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सौगात देने और नगर को तहसील का दर्जा दिया जाने की मांग की है।

परीक्षा परिणामों में लगातार देरी, व्यवस्थाएं ठप

एनएसयूआई ने उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन, विश्वविद्यालय में पारदर्शिता और छात्र हितों की रक्षा की मांग

जबलपुर।

राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के पदाधिकारियों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं, परीक्षा परिणामों में लगातार देरी और छात्रहितों की अनदेखी के विरोध में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि समय पर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो रहीं और घोषित परिणामों में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। छात्रनेता अनुराग शुक्ला और शफी खान ने बताया कि हाल ही में घोषित एमबीए परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में छात्रों को अनुत्तीर्ण कर दिया गया, जिससे विद्यार्थियों में आक्रोश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष में विभिन्न परीक्षा परिणामों में त्रुटियां सामने आई हैं, लेकिन सुधार के ठोस कदम नहीं उठाए गए। छात्रावासों की बदहाल स्थिति पर भी एनएसयूआई ने चिंता जताई। संगठन के अनुसार भवन जर्जर हैं, कमरों की छतों का प्लास्टर झड़ रहा है, सरिया बाहर निकल आए हैं, शौचालयों की नियमित सफाई नहीं हो रही और वाटर कूलर खराब पड़े हैं। दो वर्षों से सुरक्षा गार्ड न होने से छात्र-छात्राएं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एनएसयूआई ने 9 वर्षों से लंबित छात्रसंघ चुनाव शीघ्र कराने की मांग भी उठाई। संगठन का कहना है कि छात्रसंघ चुनाव नेतृत्व क्षमता और छात्र अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। ज्ञापन सौंपते समय युग ठाकुर, अनिकेत तिवारी, राजीव श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

मालवीय चौक पर कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग

जबलपुर। मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में शनिवार को मालवीय चौक पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का पुतला दहन किया गया। परिषद के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह तेकाम ने आरोप लगाया कि मंत्री द्वारा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष उमंग सिंगार के प्रति आपत्तिजनक एवं अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया गया, जो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि मंत्री के बयान से आदिवासी समाज में व्यापक आक्रोश है। इसी के विरोध में जबलपुर में परिषद के साथ अन्य सामाजिक संगठनों—जयस, सर्व आदिवासी संघ एवं भीम आर्मी—ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन कर पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि मंत्री पर एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, उन्हें मंत्री पद से हटाया जाए तथा वे सार्वजनिक रूप से आदिवासी समाज से माफी मांगें। प्रदर्शन में राजेन्द्र तेकाम, दीपेंद्र मरकाम, रामकुमार सैयाम, इंद्रकुमार कुलस्ते, कपिल मार्को, घनश्याम यादव, उदय मरावी, बालकृष्ण उइके, अनिल परस्ते, रमा धुर्वे, संजू लाल झारिया, उमा उइके, अंजना इनवाती, भरत सिंह उइके, राजू परस्ते, अजय परते, धनराज पुसाम एवं महेन्द्र मरावी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महानगर के 1041 बूथों पर सुना जाएगा 'मन की बात' कार्यक्रम

जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी जबलपुर महानगर के कार्यकर्ता रविवार 22 फरवरी को प्रातः 11 बजे शहर के सभी 1041 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुनेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने बताया कि मध्यप्रदेश के लोकनिर्माण मंत्री राकेश सिंह पश्चिम विधानसभा के बाबूराव परांजपे वार्ड स्थित बूथ क्रमांक 276 (रॉबिन जग्गी निवास) पर कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर एवं महापौर जगतबहादुर सिंह 'अन्नू' पूर्व विधानसभा के मुखर्जी मंडल अंतर्गत द्वारकानगर बूथ क्रमांक 180 (मंटू शर्मा निवास) पर मौजूद रहेंगे। प्रदेश कोषाध्यक्ष अखिलेश जैन दीनदयाल मंडल में, विधायक अभिलाष पांडे विवेकानंद मंडल अंतर्गत सुभद्राकुमारी चौहान वार्ड के बूथ क्रमांक 198 (रवि पटेल निवास) पर कार्यक्रम सुनेंगे। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अश्विनी परांजपे भाजपा संभागीय कार्यालय रानीताल में कार्यकर्ताओं के साथ 'मन की बात' सुनेंगी। जिला अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अपने-अपने बूथों पर आमजन के साथ कार्यक्रम सुनने की अपील की है।

आचार्यश्री विद्यासागर कप जैन प्रीमियर लीगः 11वां दिन रोमांच से भरपूर, सुपर-16 का आगाज़

जबलपुर

आचार्य श्री विद्यासागर कप जैन प्रीमियर लीग के 11वें दिन से सुपर-16 चरण की शुरुआत हुई। दिन भर खेले गए चार रोमांचक मुकाबलों ने क्रिकेट प्रेमियों को उत्साह से भर दिया। मुख्य अतिथि आईएएस जतिन जैन, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन इंदौर के महासचिव विनय जैन, महाकोशल-विंध्य रीजन अध्यक्ष सीए मनोज जैन तथा निकिता दुबे राय सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। सोशल ग्रुप के पदाधिकारी प्रफुल्ल जैन, प्रदीप जैन, आलोक जैन, हेमंत जैन, सुनील जैन, संजय चौधरी जैन, पवन जैन, प्रदीप बेंटिया, पंकज जैन, सोनू जैन, अभिषेक जैन, सनद जैन, अतुल जैन, अंकित जैन, राविज जैन, आनंद जैन, अभिलाष जैन, डॉ. कीर्ति जैन एवं दिनेश जैन भी मौजूद रहे।

मैदान पर खिलाड़ियों ने अनुशासन, खेल भावना और टीमवर्क का शानदार प्रदर्शन किया। कई मुकाबले अंतिम ओवर तक पहुंचे, जिससे दर्शकों में रोमांच चरम पर रहा। बेहतरीन बल्लेबाज़ी, कसी हुई गेंदबाज़ी और चुस्त फील्डिंग ने लीग की प्रतिस्पर्धात्मकता को और मजबूत किया। आचार्य श्री विद्यासागर कप जैन प्रीमियर लीग केवल एक खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि समाज में एकता, अनुशासन और सौहार्द का संदेश देने का माध्यम भी बन रही है। आगामी मुकाबलों में भी इसी तरह के रोमांचक खेल की उम्मीद जताई जा रही है।

श्रीमती माया पांडेय- राहुल टाउनशिप फेज 2 निवासी श्रीमती माया पांडेय उम्र 65 का निधन हो गया है वे आरएच पांडे की पत्नी एवं प्रभात और श्रीमती श्रद्धा की माँ थी। अंतिम यात्रा उनके निज निवास से आज रविवार को सुबह 11 बजे ग्वारीघाट मुक्तिधाम के लिए रवाना होगी।

श्री सुरजीत सिंह बग्गा- मदनमहल गुप्तेश्वर वार्ड निवासी श्री सुरजीत सिंह बग्गा (82) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में किया गया।

श्रीमती तेज कौर बग्गा- मदनमहल गुप्तेश्वर वार्ड निवासी श्री सुरजीत सिंह बग्गा की धर्मपत्नी श्रीमती तेज कौर बग्गा (76) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में संपन्न हुआ।

श्री नरेश कुमार साहू- ग्रीन सिटी माढ़ोताल निवासी दीक्षितपुरा वाले श्री नरेश कुमार साहू (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार माढ़ोताल मोक्षधाम में किया गया।

श्री अनिल पासी- नरसिंह मंदिर शास्त्री ब्रिज के पास निवासी श्री अनिल पासी (54) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री गया राम- नरसिंह वार्ड मदनमहल निवासी श्री गया राम (70) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गुप्तेश्वर मोक्षधाम में किया गया।

श्रीमती प्रियंका तेकाम- मिलौनीगंज सुभाष टाकीज के पास निवासी श्रीमती प्रियंका तेकाम (24) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती माया बाई कोष्टा- फूटाताल कोष्टा मोहल्ला निवासी श्री मदन कोष्टा की धर्मपत्नी श्रीमती माया बाई कोष्टा (55) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती चंपा देवी शर्मा- न्यू कंचनपुर अधारताल निवासी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती चंपा देवी शर्मा (64) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्रीमती कुसुम रजक- मिलौनीगंज छोटा फुहारा निवासी श्री गनेश रजक की धर्मपत्नी श्रीमती कुसुम रजक (59) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार करियापाथर श्मशान भूमि में किया गया।

श्रीमती प्रेमवती बाई- गली नं. 22, सदर निवासी श्री कन्हैया लाल की धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमवती बाई (83) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री प्रभाकर गुरव- धनवंतरी नगर निवासी श्री प्रभाकर गुरव (90) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।

श्रीमती रामकली बाई पटेल- ललपुर रोड गौरीघाट निवासी श्री देवी प्रसाद पटेल की धर्मपत्नी श्रीमती रामकली बाई पटेल (83) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री राकेश शर्मा- द्वारका नगर चुंगी चौकी रोड निवासी श्री राकेश शर्मा (63) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।

श्री सुभाष- बदनपुर शक्तिनगर निवासी श्री सुभाष (64) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में संपन्न हुआ।

श्री अमरदीप- बिलहरी मंडला रोड निवासी श्री अमरदीप (46) का निधन हो गया। अंतिम संस्कार गौरीघाट मुक्तिधाम में किया गया।

मूल्यांकन कार्य में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाईः जिला शिक्षा अधिकारी

जबलपुर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के अंतर्गत कक्षा 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं का प्रथम चरण मूल्यांकन 22 फरवरी (रविवार) से प्रारंभ होगा। इसके पूर्व 21 फरवरी 2026 को शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 184 मूल्यांकनकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने प्रशिक्षण को संबोधित करते हुए कहा कि मूल्यांकन कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रथम चरण में अंग्रेजी, भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान के तत्व विषयों की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वर्ष मूल्यांकनकर्ताओं की उपस्थिति मंडल के अधिकृत मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज होगी तथा प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को न्यूनतम 45 उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही निर्धारित समय-सीमा में निष्पक्ष एवं पारदर्शी मूल्यांकन करते हुए अंकों की ऑनलाइन फीडिंग तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने चेतावनी दी कि त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन पर मंडल द्वारा 100 प्रति अंक तथा 1000 प्रति प्रकरण तक आर्थिक दंड सहित आवश्यकतानुसार विभागीय जांच की कार्रवाई की जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान मूल्यांकन केंद्र के प्रेक्षक राममोहन तिवारी ने पूर्ण निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया और मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहने की जानकारी दी। परीक्षा प्रभारी एवं सहायक संचालक राजकुमार बधान ने मूल्यांकन ऐप की कार्यप्रणाली समझाते हुए तकनीकी मार्गदर्शन दिया। मूल्यांकन केंद्र अधिकारी एवं प्राचार्य श्रीमती रुक्मणी कनोजिया ने बताया कि प्रथम चरण में लगभग 100 मूल्यांकनकर्ता प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक कार्य करेंगे। कार्यक्रम में एम.एल.बी. स्कूल की प्राचार्य श्रीमती प्रभा मिश्रा, विधि प्रभारी कृष्णकांत शर्मा, मास्टर ट्रेनर्स एवं जिले के विभिन्न विकासखंडों से आए मूल्यांकनकर्ता उपस्थित रहे।

नाम व पता सुधार

मैं शपथकर्ता, 15106705K, Rank- Ex. TS/NK, Name- Lok Singh Soni, उम्र लगभग 58 वर्ष, पिता Late Bhim Singh Soni, पता- H.No. 148, Umariya, New Ward No. 79, Pipariya, PS- Khamaria, Dist.- Jabalpur, M.P.- 482005 शपथ पूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूं- यह कि, मैं शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थाई निवासी हूं। यह कि मैं शपथकर्ता भारतीय थल सेना से दिनांक 01/08/2003, SQD- 177/59 को सेवानिवृत्त हुआ हूं। यह कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा नाम Lok Singh एवं मेरे पिता का नाम Bhim Singh दर्ज है जिसमें मेरे एवं मेरे पिता का सरनेम Soni दर्ज नहीं है । तथा मेरा पुराना पता- Katanggar, Umaria, Khamaria, Jabalpur, दर्ज है। यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड एवं बैंक के पासबुक में मेरा नाम Lok Singh Soni एवं मेरे पिता का नाम Bhim Singh Soni तथा मेरा नया पता- H.No. 148, Umariya, New Ward No. 79, Pipariya, PS- Khamaria, Dist.- Jabalpur, M.P.- 482005 दर्ज है जो कि सत्य व सही है। यह कि Lok Singh एवं Lok Singh Soni ये दोनों ही नाम मेरे ही है, तथा Bhim Singh एवं Bhim Singh Soni ये दोनों ही नाम मेरे पिता के ही है, किसी अन्य व्यक्ति के नहीं है। यह कि मेरे सर्विस रिकॉर्ड में मेरा पूरा व सही नाम Lok Singh Soni तथा मेरे पिता का पूरा व सही नाम Bhim Singh Soni तथा मेरा नया पता- H.No. 148, Umariya, New Ward No. 79, Pipariya, PS- Khamaria, Dist.- Jabalpur, M.P.- 482005 दर्ज किया जावे। अतः भविष्य में मुझे Lok Singh Soni तथा मेरे पिता का पूरा व सही नाम Bhim Singh Soni के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा- लिखा व समझा जावे। इस हेतु शपथपत्र प्रस्तुत है।

इस युद्धाभ्यास में 277 अत्याधुनिक हथियारों का किया जाएगा प्रदर्शन

150 किलो का रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट पहली बार नजर आएगा सार्वजनिक रूप से

80 फाइटर जेट और 45 हेलीकॉप्टर दिखाएंगे अपनी ताकत

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

आने वाले 27 फरवरी को पाकिस्तान की धड़कने कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि पोखरण में वायु वीर मरुस्थल में गिराने वाले हैं बम, गोला और बारूद।

आपको बता दें कि एयर चीफ ने साफ तौर पर कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और इसी को देखते हुए वायुसेना वायु शक्ति नाम के कार्यक्रम का आयोजन करके भारी बमबारी करेगी। जिस तरह से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था ठीक उसी तरह से पाकिस्तान के बॉर्डर के समीप दुश्मन के ठिकानों को चुन-चुनकर नेस्तनाबूद करने की प्रैक्टिस होगी। 24 फरवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल और 27 फरवरी को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

इस युद्धाभ्यास में 80 फाइटर जेट्स और 45 हेलिकॉप्टर तैनात रहेंगेष करीब 12 हजार किलो गोला-बारूद का इस्तेमाल किया जाएगा। एयर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस युद्धाभ्यास में 277 अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया जाएगा।

यह है आरपीए की खासियत

पहली बार 150 किलो का रिमोटली पायलेटेड एयरक्राफ्ट यानी आरपीए सार्वजनिक रूप से दिखेगा। यह आरपीए बाज की तरह घंटों मंडराकर टारगेट मिलते ही हमला करता है। शॉर्ट रेंज लोइटरिंग म्यूनिशन और कामिकेज ड्रोन भी दिखाए जाएंगे। काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी सी-यूएएस की क्षमता का प्रदर्शन होगा। पोखरण में यह पहला मौका होगा जब फाइटर जेट, हेलिकॉप्टर, ड्रोन और मेक इन इंडिया से बने आर्म्स की साझा ताकत देखने को मिलेगी।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक बॉर्डर के पास इंडियन एयरफोर्स 27 को करेगी युद्धाभ्यास

यह है ऑपरेशन सिंदूर

6-7 मई 2025 की रात भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों के खिलाफ किया गया एक सटीक हवाई हमला था। यह कार्यवाही अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ एक त्वरित और रणनीतिक प्रतिक्रिया थी, जिसमें 9 मुख्य आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया था।

हैदराबाद हाउस में दोनों देशों के राष्ट्रप्रमुखों के बीच हुआ समझौता

भारत और ब्राजील के बीच 20 अरब डॉलर व्यापार का लक्ष्य, दोनों देशों ने साइन किए कई एमओयू

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नई दिल्ली

अमेरिका के बाद भारत और ब्राजील के बीच भारत और ब्राजील के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लेकर कई व्यापार समझौता हुआ, दोनों देशों ने कई एमओयू साइन किए। शनिवार को दिल्ली में दोनों देशों के बीच बैठक हुई है। इस दौरान साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। पिछले साल यानी 2025 में भारत और ब्राजील के बीच 15.21 अरब डॉलर तक व्यापार हुआ था। इसमें 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

भारत का एक्सपोर्ट 8.35 अरब डॉलर और ब्राजील से इंपोर्ट 6.85 अरब डॉलर तक रहा। इसके अलावा ब्राजील में भारतीय निवेश 15 अरब डॉलर से ज्यादा रहा। बता दें कि इन दिनों ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और उनका प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर हैं। शनिवार को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा की उपस्थिति में भारत और ब्राजील के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।

ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर खोलेगा भारत

बताया गया कि भारत, ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्टक्चर के लिए एक सेंटर खोलने पर काम कर रहा है। 'एआई, सुपरकंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को प्राथमिकता भारत प्राथमिकता दे रहा है। दोनों देशों का मानना है कि टेक्नॉलाजी समावेशी होनी चाहिए। इसे दोनों देशों के लिए ब्रिज की तरह काम करना चाहिए।

पीएम मोदी बोले- साझा प्रगति के लिए एक सेतु जैसा काम करना चाहिए

भारत दौरे पर हैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला और उनका प्रतिनिधिमंडल

यह कहा मोदी ने

इस दौरान, पीएम मोदी ने कहा कि यह समझौता मजबूत सप्लाई चेन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ब्राजील लैटिन अमेरिका में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हम अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा व्यापार सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। यह भरोसे का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि हम ब्राजील में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सुपरकंप्यूटर, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोनों देशों का मानना है कि प्रौद्योगिकी समावेशी होनी चाहिए और साझा प्रगति के लिए एक सेतु का काम करना चाहिए।

चीन की निर्भरता कम करने की तैयारी में भारत-ब्राजील

क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स से जुड़ा समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का एक प्रमुख हिस्सा है, जो ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की निर्भरता कम करने, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट करने और विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह समझौता दोनों देशों को कच्चे माल के निर्यातक से आगे बढ़ाकर प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और रिसाइक्लिंग में भागीदार बनाने पर जोर देता है।

यह नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात ब्राजील के राष्ट्रपति

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने कहा, 'मेरे प्रिय मित्र मोदी, इस देश में छठी बार आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत और ब्राजील की यह मुलाकात बेहद खास है। हम सिर्फ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें ही नहीं हैं, बल्कि यह एक डिजिटल शक्ति और एक नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मुलाकात है।'उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील दोनों ही विविधताओं से भरे बड़े देश हैं, सांस्कृतिक उद्योग के बड़े केंद्र हैं और हम दोनों शांति का समर्थन करते हैं। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ दा नोब्रेगा ने बताया कि राष्ट्रपति लूला भारत की राजकीय यात्रा पर 11 कैबिनेट मंत्रियों, 300 से अधिक कारोबारियों और 50 सीईओ के बड़े प्रतिनिधिमंडल के साथ आए हैं।

दिल्ली में 'लश्कर' के हमले की चेतावनी

निशाने पर धार्मिक-ऐतिहासिक जगह

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी लाल किले के आसपास एक बार फिर धमाके की साजिश रच सकते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक के एक प्रमुख मंदिर को भी निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर के आतंकी 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद भारत में भी खौफनाक साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जैसे ही यह इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस ने तुरंत लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

आतंकी हमले के इनपुट के बीच हाई अलर्ट पर पुलिस

इधर, पंजाब और कश्मीर में दो एलईडी बरामद

पंजाब और कश्मीर में दो अलग-अलग स्थानों पर आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। यह बरामदगी ऐसे समय हुई है जब दिल्ली में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की ओर से हमले की चेतावनी मिली है। पंजाब के अमृतसर में शुक्रवार को रेया पुलिस पोस्ट के पास एक संदिग्ध बैग मिला। पुलिस ने मौके पर बम निरोधक दस्ता बुलाकर जांच की। अमृतसर के एसएसपी सोहेल कासिम मीर ने बताया कि बैग के अंदर आईईडी पाया गया, जिसे बाद में सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। वहीं, कश्मीर के गांदरबल जिले के सफापोरा इलाके में भी इसी दिन एक आईईडी बरामद हुआ। सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम ने इसे भी कुछ ही घंटों में निरस्त कर दिया. यह उत्तर कश्मीर में इस सप्ताह तीसरी आईईडी गिरफ्तारी है, क्योंकि गुरुवार को तंगमार्ग रोड और बारामूला में भी आईईडी मिला था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए मुआवजे का दिया आदेश

'कैदी की आत्महत्या राज्य पूरी तरह जिम्मेदार'

एजेंसी ▶▶ प्रयागराज

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कैदी की हिरासत में अप्राकृतिक तरीके से मौत होती है, तो उसके लिए पूरी तरह से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी, भले ही वह मृत्यु आत्महत्या ही क्यों न हो। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार एक आंतरिक और सर्वव्यापी अधिकार है। जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने 20 फरवरी को प्रेमा देवी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। प्रेमा देवी ने पीलीभीत जिला जेल में अपने नाबालिग बेटे की मौत के लिए मुआवजे की मांग की थी।

मुआवजा देने का निर्देश

अदालत ने प्रतिवादियों- राज्य सरकार और अन्य अधिकारियों को तीन सप्ताह के भीतर कानूनी वारिसों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से मुआवजे के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश तैयार करने को भी कहा। फैसले के अनुसार, याचिकाकर्ता के बेटे, जो पॉक्सो मामले में विचाराधीन था। उसने 20 फरवरी, 2024 को आत्महत्या कर ली। उसका शव जेल के शौचालय के वेंटिलेटर से लटका हुआ मिला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पहले तीन लाख रुपये के मुआवजे की सिफारिश की थी। मुआवजा न मिलने पर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मृतक को अवैध पैसों की मांग को लेकर पुलिसकर्मियों द्वारा प्रताड़ित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई।

दोनों टीमों को एक-एक अंक मिले, सेमीफाइनल के लिए सभी मैच जीतना जरूरी

टी-20 विश्व कप: पाकिस्तान-न्यूजीलैंड सुपर-8 मैच बारिश में धुला

- सेमीफाइनल की रेस में क्या असर होगा?

पहला सुपर-8 मैच रद्द होने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को एक-एक अंक मिले हैं। यहां से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमों को अपने बचे हुए दोनों मैच जीतने होंगे। दोनों टीमों को इंग्लैंड और श्रीलंका से खेलना है।

टी-20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का पहला सुपर-8 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया है। शनिवार शाम 6:30 बजे पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। लेकिन, मैच शुरू होने से पहले बारिश आ गई।

करीब ढाई घंटे के इंतजार के बार मैच रेफरी ने इसे रद्द कर करने का फैसला लिया। ऐसे में दोनों टीमों को एक-एक अंक दे दिए। इस टूर्नामेंट में दूसरा मैच रद्द हुआ है। इससे पहले जिम्बाब्वे और आयरलैंड का मैच रद्द हुआ था।

सुपर-8 ग्रुप-2 पॉइंट्स टेबल

टीम	मैच	जीत	हार	NR	पॉइंट्स	रन रेट
न्यूजीलैंड	1	0	0	1	1	0
पाकिस्तान	1	0	0	1	1	0

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

पाकिस्तानः सलमान आगा (कप्तान), साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, बाबर आजम, फखर जमान, उस्मान खान (विकेटकीपर), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक।

न्यूजीलैंडः फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी और लॉकी फर्ग्यूसन।

सीएम सुक्खू की तबीयत बिगड़ी, एम्स ले गए

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शनिवार की सुबह के दिल्ली में बीमार पड़ गए। हल्के दर्द के बाद वह दिन में करीब 12 बजे उपचार के लिए एम्स दिल्ली पहुंचे। टेस्ट कराने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल सदन लौट आए हैं। अब उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है। हालांकि, सीएम के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन का अभी इंतजार है। सूचना के अनुसार- सीएम के पेट में सुबह के वक्त अचानक दर्द उठा। जैसे ही थोड़ा ज्यादा हुआ तो वह अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू हुआ और टेस्ट करवाए गए। उनकी सभी रिपोर्ट सही बताई जा रही है और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।

यूनेस्को विश्व धरोहर को लेकर एएसआई ने लिया फैसला

हर रोज खुलेगा अब लाल किला, जारी हुआ आदेश

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक लाल किला अब सप्ताह के सभी दिन आगंतुकों के लिए खुला रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। पहले यह मुगलकालीन स्मारक प्रत्येक सोमवार को बंद रहता था। लाल किला एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। एएसआई ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। यह आदेश हाल ही में जारी किया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आदेश के अनुसार लाल किला सोमवार को भी खुला रहेगा। यह आदेश 16 फरवरी से प्रभावी हो गया है। 16 फरवरी को लाल किला खुला था। आदेश पर एएसआई के महानिदेशक के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश 13 फरवरी को जारी किया गया था। एएसआई देश के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों का प्रबंधन करता है।

नए आदेश का प्रभाव

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लाल किले को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। इस नए आदेश से पर्यटकों को काफी सुविधा मिलेगी। अब वे सप्ताह के किसी भी दिन लाल किले का भ्रमण कर सकेंगे। पहले सोमवार को लाल किला बंद होने के कारण कई पर्यटक निराश होते थे। यह निर्णय पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होगा।

ऐतिहासिक महत्व और प्रबंधन

लाल किला दिल्ली का एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। यह मुगलकालीन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस महत्वपूर्ण स्मारक का रखरखाव करता है। एएसआई देश भर में कई अन्य संरक्षित स्मारकों का भी प्रबंधन करता है।

4 मार्च से ठंडे जल से स्नान करेंगे महाकाल

हरिभूमि न्यूज ▶▶ उज्जैन

होली के अवसर से राजाधिराज महाकाल ठंडे जल से स्नान करेंगे। इसके पहले अभी तक बाबा महाकाल को गरम जल से स्नान कराया जाता रहा। बाबा महाकाल ठंड के दौरान गरम जल से और गर्मी के मौसम के दौरान ठंडे पानी से स्नान करते है। ठंडे जल से स्नान कराने की शुरूआत चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 4 मार्च से होगी। इसके साथ ही तीन आरतियों के समय में भी बदलाव हो जाएगा। मंदिर में प्रतिदिन पांच आरतियां होती हैं। महाकाल मंदिर में गर्मी के मौसम के दौरान दिनचर्या बदलेगी और यह सिलसिला शरद पूर्णिमा तक जारी रहेगा। महाकाल मंदिर की पूजन परंपरा में साल में दो बार भगवान महाकाल की दिनचर्या व आरती का समय बदलता है।

पत्नी की आरटीआई याचिका खारिज

पति के वेतन का विवरण निजी सूचना, जानना पत्नी का हक नहीं

राजस्थान हाइकोर्ट का बड़ा फैसला

एजेंसी ▶▶ जयपुर

राजस्थान हाइकोर्ट ने राज्य सरकार का आदेश बरकरार रखा, जिसमें पत्नी द्वारा दायर सूचना अधिकार आवेदन के तहत पति के वेतन संबंधी विवरण देने से इनकार किया गया था। अदालत ने कहा कि किसी कर्मचारी के वेतन और सेवा संबंधी विवरण व्यक्तिगत सूचना की श्रेणी में आते हैं। मामले में याचिकाकर्ता ने संबंधित विभाग में कार्यरत अपने पति के एक निश्चित अवधि के वेतन पर्ची और वेतन भुगतान का विवरण मांगा। राज्य ने यह कहते हुए सूचना देने से इनकार किया कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है, जो एक तृतीय पक्ष से संबंधित है और सूचना अधिकार के तहत अपवाद में आती है। इसके बाद याचिका हाइकोर्ट में दायर की गई। जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि राज्य द्वारा सूचना देने से इनकार करने के आदेश में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि मांगी गई सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी है।

बेरोजगार युवाओं को उठाना पड़ा व्यवस्थाओं की लेटलतीफी का खामियाजा

कैग की रिपोर्ट में खुलासा, लोक सेवा आयोग की लापरवाही से 30 दिन की भर्ती प्रक्रिया में औसतन 136 दिन तक लगे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राज्य सरकार ने शुक्रवार को वर्ष 2025 की भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में अलग-अलग विभागों की आडिट में बड़े पैमाने पर अनियमितता पकड़ी है। लोक सेवा आयोग की ऑडिट में पाया कि जो परीक्षा 30 दिनों के भीतर होनी चाहिए थी, उसमें आयोग को 136 दिन लग गए।

इससे बड़े पैमाने पर लेटलतीफी हुई। इसका खामियाजा बेरोजगार युवाओं को भुगतना पड़ा। कैग ने लोक सेवा आयोग के विभिन्न विभागों खासकर 2018-19 से लेकर 2022-23 की अवधि के लिए अभिलेखों की नमूना जांच की। इसमें पाया कि आयोग व राज्य सरकार के विभागों के बीच समन्वय की कमी पाई गई। क्योंकि विभागों की ओर से नियुक्तियों की सूचना देने में विलंब किया गया। इसके परिणाम स्वरुप भर्ती में देरी हुई। आयोग के ऑडिट में पाया कि 2018 से लेकर 2023 के दौरान 44 परीक्षाओं में से 28 परीक्षाओं में ही विज्ञप्ति जारी किया। यह योजना में कमी को दर्शाता है। आयोग ने 94 विज्ञापनों में से 30 विज्ञापन जारी करने में एक माह की उचित अवधि के अतिरिक्त औसतन 136 दिन लिए।

19 परीक्षाओं में से केवल पांच का आयोजन ऑनलाइन मोड पर किया

ऑडिट में कैग ने यह भी पाया कि 19 परीक्षाओं में से केवल पांच का आयोजन ऑनलाइन मोड पर किया गया। 2013 से अपनी नियमावली को अद्यतन नहीं किया। जिसके कारण शासन के निर्देशों को उसमें शामिल नहीं किया गया आयोग का वित्तीय प्रबंधन त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि 42% निधि का समर्पण किया गया। 2018 से 2023 के बीच में 51.18 करोड़ में से करीब 5 करोड रुपए का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इस दौरान 21 से 24% के बीच मानव संसाधन की कमी थी। इसे संविदा कर्मचारियों से भरा गया था। आयोग ने 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी आवेदकों को परीक्षा शुल्क को वापस नहीं किया। इसके अलावा भी आयोग में कई बड़ी अनियमितताएं कैग ने पकड़ी है।

विज्ञापन प्रकाशित करने में 20 माह का समय ले लिया

आयोग ने विज्ञापन की तिथि से क्रमशः एक स्तरीय दो स्तरीय और त्रि स्तरीय परीक्षाओं के लिए 6, 12, 18 माह के निर्धारित समय की तुलना में 1 से 25 माह के विलंब के साथ चयन की प्रक्रिया पूर्ण की। एक मामले में यह भी पाया गया कि आयोग ने मांग प्राप्त करने के बाद भी विज्ञापन प्रकाशित करने में 20 माह का समय ले लिया। आयोग ने परिवहन विभाग के एक मामले में त्रुटि बस दो बार सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के 13 पदों की मांग भेजी और आयोग ने अभ्यर्थियों का चयन किया, जो आंतरिक नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। जबकि आयोग या विभाग स्तर पर ऐसी गलतियों को रोका जा सकता था। सामान्य प्रशासन विभाग ने समय पर राय या आदेश जारी नहीं किया, जिसके कारण आयोग ने डीपीसी के 47 मामलों में कार्रवाई नहीं की। इसके कारण पदोन्नति में विलंब हुआ।

सुरक्षित निवेश के कई मजबूत विकल्प, मिलेगा बढ़िया रिटर्न

- पीपीएफ, एनएससी, एससीएसएस और सुकन्या जैसी योजनाएं दे रही हैं आकर्षक ब्याज और टैक्स लाभ
- कम जोखिम में स्थिर आय और लंबी अवधि में मजबूत फंड बनाने के विकल्प
- बैंक एफडी से आगे बढ़कर सोचें, सरकारी योजनाओं में छिपा है बेहतर रिटर्न

बिजनेस डेस्क

आज के दौर में निवेशकों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है पूंजी की सुरक्षा और स्थिर रिटर्न। शेयर बाजार की अस्थिरता से घबराने वाले या जोखिम कम लेना चाहने वाले लोग आमतौर पर बैंक एफडी का सहारा लेते हैं। लेकिन क्या एफडी ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प है? असल में, सरकार समर्थित कई ऐसी योजनाएं हैं जो न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि कई मामलों में एफडी से बेहतर ब्याज भी देती हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही भरोसेमंद निवेश विकल्पों के बारे में, जहां सुरक्षा के साथ अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है।

कंपाउंडिंग के लिए सबसे बेहतर

1. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि में सुरक्षित तरीके से बड़ा फंड बनाना है, तो पीपीएफ एक बेहतरीन विकल्प है।

- निवेश अवधिः 15 वर्ष
- वर्तमान ब्याज दर : 7.1% (सरकार द्वारा तिमाही आधार पर तय)
- अधिकतम निवेश : 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष
- टैक्स लाभ : धारा 80सी के तहत छूट
- पीपीएफ की सबसे बड़ी खासियत है इसका ईईईई स्टेटस निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों टैक्स-फ्री होती हैं। यह योजना खासकर उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो रिटायरमेंट या बच्चों की उच्च शिक्षा जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं।

2. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी)

- यदि आप 5 साल की अवधि के लिए सुरक्षित निवेश चाहते हैं, तो एनएससी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- निवेश अवधि : 5 वर्ष
- ब्याज दर : लगभग 7.7%
- टैक्स लाभ : 80सी के तहत छूट
- एनएससी में निवेश की गई राशि सुरक्षित रहती है और तय ब्याज दर के अनुसार परिपक्वता पर रिटर्न मिलता है। यह योजना उन लोगों के लिए बेहतर है जो मध्यम अवधि के लक्ष्य के लिए निवेश करना चाहते हैं और जोखिम नहीं लेना चाहते।

3. सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (एससीएसएस)

- यह योजना विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए है।
- निवेश अवधि : 5 वर्ष (आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है)
- ब्याज दर : लगभग 8% से अधिक (तिमाही समीक्षा के अधीन)

नियमित ब्याज भुगतान

- एससीएसएस उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने रिटायरमेंट फंड से नियमित आय चाहते हैं। ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, जिससे नकदी प्रवाह बना रहता है।

4. पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (एमआईएस)

- अगर आप सुरक्षित निवेश के साथ हर महीने नियमित आय चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम एक बेहतर विकल्प है।
- निवेश अवधिः 5 वर्ष
- ब्याज दरः लगभग 7.4%
- मासिक ब्याज भुगतान

5. सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)

- बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना विशेष रूप से बनाई गई है।
- पात्रताः 10 वर्ष या उससे कम आयु की बेटी
- निवेश अवधिः 15 वर्ष
- मैच्योरिटीः 21 वर्ष
- अधिकतम निवेशः 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष
- ब्याज दरः लगभग 8.2%
- एसएसवाई वर्तमान में सबसे अधिक ब्याज देती है।

एसआईपी संपत्ति निर्माण का एक आसान और व्यवस्थित तरीका बिना योजनाबद्ध निकासी निवेश को कर देती है बर्बाद

सिर्फ एसआईपी नहीं एसडब्लूपी भी जरूरी

बिजनेस डेस्क

जनवरी 2026 में निवेशकों ने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के जरिए म्यूचुअल फंड में 31,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। एसआईपी अब आदत जैसी बन गई है। यह संपत्ति निर्माण का एक आसान और व्यवस्थित तरीका बन गया है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आप इसका उपयोग करना शुरू करते हैं। बिना योजनाबद्ध निकासी रणनीति के वर्षों का अनुशासित निवेश जल्दी ही बिखर सकता है। इसलिए हर एसआईपी के साथ एक सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान (एसडब्लूपी) होना भी जरूरी है। एसआईपी संपत्ति संचय का एक प्रभावी साधन है, लेकिन यह सुचारु परिणाम की गारंटी नहीं देता। इसलिए एसआईपी से बाहर निकलने का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका एसआईपी कितने समय तक चला या आपने इसे किस बाजार परिस्थिति में शुरू किया। अंतिम चरण में बाजार में गिरावट आपकी योजनाओं को पटरी से उतार सकती है। मान लीजिए एक निवेशक ने जनवरी 2005 में एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड में 10,000 रुपये की मासिक एसआईपी शुरू की। लक्ष्य था 2020 के मध्य तक घर की डाउन पेमेंट के लिए 40 लाख रुपये जुटाना। 31 जनवरी 2020 तक 18 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 40.73 लाख रुपये हो गया। लक्ष्य आसानी से हासिल होता दिख रहा था। फिर महामारी के कारण बाजार में गिरावट आई। 23 मार्च 2020 तक यह कॉर्पस घटकर 26 लाख रुपये रह गया यानी अचानक 14 लाख रुपये की कमी। पोर्टफोलियो को दोबारा संभलने में लगभग आठ महीने लग गए। यदि निवेशक ने लक्ष्य तिथि से 12-18 महीने पहले एसडब्लूपी के माध्यम से चरणबद्ध निकासी शुरू कर दी होती तो कुछ मुनाफा सुरक्षित किया जा सकता था। एसडब्लूपी मूलतः एसआईपी का उल्टा है। नियमित अंतराल पर निश्चित रकम निवेश करने के बजाय आप तय समयावधि में नियमित रूप से निश्चित राशि निकालते हैं। जैसे-जैसे लक्ष्य नजदीक आता है, एसडब्लूपी एक संतुलित और क्रमिक निकासी का मार्ग तैयार करता है।

एसडब्लूपी है वितरण की संरचना

इस संरचना के दो प्रमुख लाभ हैं। पहला यह अंतिम समय की बाजार अस्थिरता से अर्जित लाभ के एक हिस्से की सुरक्षा करता है। दूसरा जो राशि नहीं निकाली जाती, वह निवेशित बनी रहती है और अंतिम चरण में संभावित बढ़त का लाभ उठाती है। उद्योग के विशेषज्ञ अब एसआईपी और एसडब्लूपी को एक संयुक्त रणनीति के दो हिस्सों के रूप में देखते हैं। वे इस संयोजन को जीवन भर का एसआईपी बताते हैं। कमाई के वर्षों में व्यवस्थित बचत और आय कम होने पर व्यवस्थित निकासी, बिना चक्रवृद्धि की ताकत को तोड़े। असल में एसआईपी संचय का इंजन है, जबकि एसडब्लूपी वितरण की संरचना। यह दोनों मिलकर संपत्ति निर्माण, संरक्षण और वितरण का निरंतर चक्र बनाते हैं।

सेवानिवृत्ति से आगे की भी सोचें

परंपरागत रूप से एसडब्लूपी को रिटायरमेंट आय के साधन के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन यह धारणा बदल रही है। एसडब्लूपी जीवन के विभिन्न चरणों में एक लचीला और कर-कुशल नकदी प्रवाह समाधान बनकर उभर रहा है। यह लोन की ईएमआई, बच्चों की फीस या अनियमित आय से जुड़े जीवनशैली खर्च जैसे नियमित खर्चों में मदद कर सकता है। एसडब्लूपी फ्रीलांसर, कंसल्टेंट या चक्रीय आय वाले व्यवसायियों के लिए भी उपयोगी है। अधिक आय वाले महीनों में अतिरिक्त कमाई निवेश की जा सकती है, जबकि एक छोटा एसडब्लूपी निश्चित मासिक खर्चों के लिए स्थिर आय प्रदान कर सकता है। यहां तक कि एकमुश्त लक्ष्यों जैसे शादी या घर की मरम्मत के लिए भी एसडब्लूपी चरणबद्ध निकासी की सुविधा देता है, जिससे टाइमिंग जोखिम कम होता है और शेष पूंजी निवेशित बनी रहती है।

बकेट रणनीति भी बनाएं

रिटायरमेंट में हर फंड एसडब्लूपी के लिए उपयुक्त नहीं होता। विशेषज्ञ तीन-बकेट रणनीति सुझाते हैं। तीन साल के खर्च लिक्विड फंड में, चौथे से सातवें वर्ष के खर्च कंजरवेटिव हाइब्रिड फंड में और दीर्घकालिक निवेश इक्विटी में ताकि मुद्रास्फीति को मात दी जा सके। निकासी पहले बकेट से शुरू होती है। जैसे-जैसे वह कम होता है, दूसरे बकेट से उसे भरा जाता है और बाद में तीसरे बकेट से। यह स्तरीय संरचना निकट अवधि के खर्चों को इक्विटी की अस्थिरता से बचाती है और दीर्घकालिक वृद्धि को बनाए रखती है।

चक्र को पूरा करना जरूरी

हर वित्तीय यात्रा व्यक्तिगत लक्ष्यों, आय पैटर्न और जोखिम सहनशीलता से प्रभावित होती है। लेकिन सिद्धांत सार्वभौमिक है। वितरण योजना के बिना संचय अधूरा है। एसआईपी से एसडब्लूपी तक सुचारु संक्रमण आवश्यक है। सही तरीके से किया जाए तो यह साझेदारी चक्रवृद्धि की शक्ति को जारी रखते हुए आपको नियमित आय भी देती रहती है।

संक्रमण की योजना भी हो

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि निवेश के तुरंत बाद एसडब्लूपी शुरू नहीं करना चाहिए। निकासी शुरू होने से पहले पोर्टफोलियो को बढ़ने का समय चाहिए। बहुत जल्दी शुरुआत करने से यदि बाजार अस्थिर हो जाए, तो मूलधन पर असर पड़ सकता है। कर दक्षता भी इसका एक बड़ा लाभ है। प्रत्येक एसडब्लूपी किस्त में मूलधन और पूंजीगत लाभ दोनों शामिल होते हैं, लेकिन कर केवल लाभ वाले हिस्से पर लगता है। कम से कम एक वर्ष तक निकासी टालने से इक्विटी निवेश दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर के दायरे में आ जाता है, जिसमें सालाना 1.25 लाख रुपये तक के लाभ पर छूट मिलती है। अनिवार्य लक्ष्यों के लिए आदर्श रूप से लक्ष्य तिथि से 2-3 वर्ष पहले एसडब्लूपी शुरू कर देना चाहिए। भले ही कॉर्पस थोड़ा कम हो। अंतिम वर्ष तक इंतजार करने से जोखिम बढ़ जाता है। चरणबद्ध निकासी परिणामों को संतुलित बनाती है।

कितनी निकासी सुरक्षित है?

दीर्घकालिक स्थितियों जैसे सेवानिवृत्ति में निकासी दर यह तय करती है कि बचत 20-30 वर्षों तक चलेगी या समय से पहले खत्म हो जाएगी। जोखिम केवल बाजार की अस्थिरता नहीं, बल्कि सीक्वेंस-ऑफ-रिटर्न्स का भी होता है। यदि शुरुआती वर्षों में खराब रिटर्न के दौरान निकासी होती है तो कॉर्पस तेजी से घट सकता है। एसआईपी के विपरीत, जहां गिरते बाजार में अधिक यूनिट जमा होती हैं, एसडब्लूपी में गिरावट के दौरान समान नकदी प्रवाह के लिए अधिक यूनिट बेचनी पड़ती हैं। इसलिए निकासी दर संतुलित और सावधानीपूर्ण होनी चाहिए। आदर्श रूप से निकासी दर पोर्टफोलियो के दीर्घकालिक संभावित रिटर्न से कम होनी चाहिए। एक सामान्य नियम यह है कि निकासी वास्तविक रिटर्न यानी मुद्रास्फीति समायोजित रिटर्न के आधार पर तय हो। यदि अपेक्षित रिटर्न 10% और मुद्रास्फीति 5% है, तो निकासी 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्थिरता बनाए रखने के लिए निकासी दर अपेक्षित रिटर्न से 2-3 प्रतिशत अंक कम रखनी चाहिए। वैश्विक शोध अक्सर 3.5-4% को एक टिकाऊ दर मानता है, लेकिन इसकी उपयुक्तता एसेट आवंटन, जीवन प्रत्याशा और जीवनशैली की जरूरतों पर निर्भर करती है। प्रदर्शन के आधार पर समायोजित होने वाली डायनेमिक निकासी रणनीतियां भी मजबूती बढ़ा सकती हैं।

फंड तैयार करने की जल्दबाजी छोड़िए, एसआईपी को समय दें

बिजनेस डेस्क। सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) आज म्यूचुअल फंड में निवेश का सबसे लोकप्रिय तरीका बन चुका है। छोटे-छोटे मासिक निवेश के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का यह अनुशासित माध्यम है। लेकिन एक सवाल लगभग हर निवेशक के मन में आता है। एसआईपी में रिटर्न असली रफ्तार कब पकड़ता है? कई निवेशक 1-2 साल में शानदार मुनाफे की उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो वे एसआईपी बंद भी कर देते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि एसआईपी का असली फायदा समय के साथ खुलकर सामने आता है।

शॉर्ट टर्म में क्यों निराश कर सकता है एसआईपी?

अगर आप 1 से 3 साल की अवधि में एसआईपी का प्रदर्शन देखें, तो तस्वीर उतनी आकर्षक नहीं दिखती। ऐतिहासिक आंकड़ों के आधार पर निफ्टी 50 पर आधारित एसआईपी के रिटर्न का विश्लेषण बताता है कि छोटे समय में रिटर्न कई बार फ्लैट या निगेटिव भी रहा है।

कुछ अवधियों में

1. साल का एक्सआईआरआर रिटर्न -60% से ज्यादा तक गिरा
2. साल में -40% के आसपास
3. साल में -20% से ज्यादा गिरावट

शुरुआती रिटर्न कमजोर

यह सुनकर घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन इसका कारण समझना जरूरी है। शेयर बाजार साइकिल में चलता है कभी तेजी, कभी गिरावट। यदि आपने एसआईपी की शुरुआत बाजार के ऊपरी स्तर पर की और उसके बाद गिरावट आई, तो शुरुआती रिटर्न कमजोर दिख सकते हैं। इसे ही टाइमिंग रिस्क कहते हैं। शॉर्ट टर्म में बाजार की दिशा आपके निवेश अनुभव को प्रभावित करती है।

5 साल के बाद बदलती है तस्वीर

- जैसे-जैसे निवेश की अवधि 5 साल के आसपास पहुंचती है, उतार-चढ़ाव का असर कम होने लगता है।
- 5 साल के अधिकांश रोलिंग पीरियड में एसआईपी का रिटर्न 5% से 10% के बीच रहा है। लंबी अवधि में रिकवरी का मौका मिलता है।

दो चीजें काम करती हैं

- रुपया लागत औसत : बाजार गिरने पर आपकी तय राशि से ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं।
- कंपाउंडिंग : शुरुआती निवेश पर मिलने वाला रिटर्न आगे रिटर्न कमाता है।
- शुरुआती सालों की कमजोरी संतुलित होने लगती है और निवेश स्थिरता दिखाने लगता है।

7 साल के बाद बढ़ती है रफ्तार

- इतिहास बताता है कि 7 साल या उससे अधिक की अवधि में एसआईपी पर निगेटिव रिटर्न की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। डबल डिजिट रिटर्न सामान्य हो जाते हैं। यहां सबसे बड़ा बदलाव बाजार में नहीं, बल्कि निवेशक के अनुभव में आता है। बाजार गिरता है, तो आपके पास रिकवरी का पर्याप्त समय होता है। तेजी आने पर आप उस पूरी रैली का हिस्सा बनते हैं। कंपाउंडिंग का प्रभाव स्पष्ट दिखने लगता है।

ऐसे समझें

उदाहरण के तौर पर, अगर कोई निवेशक हर महीने 10,000 रुपये एसआईपी करता है और औसतन 12% रिटर्न मिलता है, तो 3 साल में कुल निवेश 3.6 लाख पर फंड लगभग 4–4.5 लाख के आसपास हो सकता है। 10 साल में कुल निवेश 12 लाख पर फंड 23–24 लाख से ज्यादा हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत।

कब शुरू करें और कितना समय दें

- जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना बेहतर।
- कम से कम 7–10 साल का नजरिया रखें।
- बाजार गिरने पर बंद न करें, जारी रखें।
- लक्ष्य आधारित निवेश करें।

असली रफ्तार कहां से

- पहले 2–3 सालः उतार-चढ़ाव
- 5 सालः स्थिरता
- 7 साल+: कंपाउंडिंग का प्रभाव
- 10 साल+: वास्तविक वेल्थ क्रिएशन

धैर्य ही असली रणनीति

एसआईपी कोई जादुई फार्मूला नहीं, बल्कि अनुशासित निवेश की प्रक्रिया है। छोटे समय में परिणाम आकर्षक न दिखें, लेकिन लंबी अवधि में यह प्रभावशाली बन जाता है। अगर आप बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने का धैर्य रखते हैं और निवेश को 7–10 साल का समय देते हैं, तो एसआईपी मजबूत संपत्ति निर्माण करेगी।

क्या एसआईपी सच में बना सकती है अमीर?

नौकरीपेशा लोगों के लिए छोटी बचत को निवेश में बदलना व्यावहारिक तरीका

अनुशासन लंबे समय में संपत्ति निर्माण की रखता है नींव

बिजनेस डेस्क

आज के दौर में हर कमाने वाला व्यक्ति चाहता है कि उसकी आय सिर्फ खर्च तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में बड़ी पूंजी में बदले। नौकरीपेशा लोगों के लिए हर महीने छोटी-छोटी बचत को निवेश में बदलना सबसे व्यावहारिक तरीका है। इसी संदर्भ में एसआईपी सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। लेकिन सवाल यह है क्या एसआईपी वास्तव में आपको अमीर बना सकती है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एसआईपी कोई निवेश उत्पाद (प्रोडक्ट) नहीं, बल्कि निवेश करने का तरीका है। असल निवेश म्यूचुअल फंड में होता है और एसआईपी उस फंड में नियमित अंतराल पर तय रकम लगाने की प्रणाली है। यानी आप हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करते हैं, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। यही अनुशासन लंबे समय में संपत्ति निर्माण की नींव रखता है। अमीर बनने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने समय तक निवेश करते हैं और कितनी निरंतरता बनाए रखते हैं। शेयर बाजार से जुड़े फंड्स में ऐतिहासिक रूप से लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन अल्पकाल में उतार-चढ़ाव स्वाभाविक है। जो निवेशक 8–10 साल या उससे अधिक का धैर्य रखते हैं, उन्हें चक्रवृद्धि का वास्तविक लाभ मिलता है। छोटी रकम भी समय के साथ बड़ी पूंजी में बदल सकती है। बशर्ते निवेश नियमित और दीर्घकालिक हो।

जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं

हालांकि, यह समझना भी जरूरी है कि एसआईपी "जल्दी अमीर बनने" का शॉर्टकट नहीं है। बाजार में गिरावट आएगी, रिटर्न कभी ज्यादा तो कभी कम होंगे। जो लोग कुछ महीनों में चमत्कार की उम्मीद करते हैं, वे अक्सर निराश होते हैं। असली ताकत अनुशासन और समय में छिपी है, न कि तात्कालिक मुनाफे में। जोखिम, रणनीति और समझदारी का संतुलन एसआईपी बाजार से जुड़ा निवेश है, इसलिए इसमें जोखिम भी शामिल है। यह फिक्स्ड डिपॉजिट या पीपीएफ की तरह पूरी तरह सुरक्षित विकल्प नहीं है। सही फंड का चयन, अपने जोखिम स्तर की पहचान और निवेश लक्ष्य की स्पष्टता बेहद जरूरी है। यदि आपका लक्ष्य 10-15 साल दूर है जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की पढ़ाई तो इक्विटी आधारित फंड उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन कम अवधि के लक्ष्य के लिए संतुलित या डेट फंड बेहतर विकल्प हो सकते हैं।

बाजार गिरने पर घबराएं नहीं

बाजार गिरने पर घबराहट में एसआईपी रोक देना सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। दरअसल, गिरावट के समय कम कीमत पर अधिक यूनिट मिलती हैं, जो बाजार सुधरने पर बेहतर रिटर्न दे सकती हैं। यही "रूपीकॉस्ट एवरेजिंग" का फायदा है। इसलिए समझदारी यही है कि उतार-चढ़ाव को निवेश यात्रा का हिस्सा मानें। एक और आम गलती है बहुत सारे फंड में निवेश कर देना। अलग-अलग सलाह के चक्कर में पोर्टफोलियो इतना जटिल हो जाता है कि निगरानी मुश्किल हो जाती है। बेहतर है कि अपने लक्ष्य के अनुसार सीमित और संतुलित फंड चुनें। गुणवत्ता पर ध्यान दें, संख्या पर नहीं। एसआईपी की एक बड़ी खूबी लचीलापन भी है। आपकी आय बढ़े तो निवेश राशि बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़े तो घटा या रोक भी सकते हैं। यह कोई कठोर अनुबंध नहीं है। लेकिन बार-बार बदलाव से बचना चाहिए; रणनीति सोच-समझकर तय करें।

यह जानना जरूरी

एसआईपी आपको रातोंरात अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन समय, अनुशासन और सही रणनीति के साथ यह मजबूत संपत्ति निर्माण का प्रभावी साधन बन सकती है। समझदारी से किया गया निवेश, धैर्य और लक्ष्य-आधारित योजना यही वह सूत्र है जो सामान्य आय वाले व्यक्ति को भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना सकता है। अमीरी केवल बड़ी कमाई से नहीं, बल्कि सही निवेश आदतों से भी आती है।

ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में यह सबसे लुभावना मौका

सस्ती किस्तों का जाल : क्या सच में 'नो कॉस्ट' है ईएमआई

ईएमआई में नहीं दिखता ब्याज, लेकिन कीमत बदल जाती है

जानकारी

बिजनेस डेस्क

ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में एक लाइन सबसे ज्यादा लुभाती है वो है 'नो कॉस्ट' ईएमआई। छोटी-छोटी किस्तें देखकर खरीदारी का फैसला आसान लगने लगता है। दिमाग कहता है "इतनी सी ईएमआई है, अभी ले लेते हैं।" लेकिन निवेश और व्यक्तिगत वित्त के नजरिए से देखें तो 'नो कॉस्ट' ईएमआई उतनी सरल नहीं, जितनी दिखाई देती है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई इसमें कोई लागत नहीं होती? या फिर लागत सिर्फ नजर नहीं आती?

'नो कॉस्ट' ईएमआई होती क्या है?

सरल शब्दों में, 'नो कॉस्ट' ईएमआई का मतलब है कि आप किसी प्रोडक्ट की कीमत किस्तों में चुकाते हैं और आपको अलग से ब्याज नहीं देना पड़ता। यानी कुल ईएमआई जोड़ने पर रकम उतनी ही होगी जितनी प्रोडक्ट की कीमत। लेकिन बैंक या फाइनेंस कंपनी बिना कमाई के पैसा उधार नहीं देती। तो फिर ब्याज कौन दे रहा है? यहीं से असली खेल शुरू होता है।

बैंक की कमाई कैसे होती है?

जब आप ईएमआई चुनते हैं, तो आमतौर पर प्रोडक्ट पर मिलने वाला सीधा डिस्काउंट कम कर दिया जाता है। उसी घटे हुए डिस्काउंट से बैंक का ब्याज एडजस्ट कर दिया जाता है। मतलब ये कि कागजों में आपको "ब्याज नहीं" दिखता है। लेकिन आपको मिलने वाला फायदा पहले ही कम कर दिया जाता है। बैंक को उसका हिस्सा मिल जाता है, और ग्राहक को लगता है कि वह बिना अतिरिक्त खर्च के सुविधा ले रहा है।

एक उदाहरण से समझिए

- मान लीजिए आप 60,000 रुपये का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं।
- फुल पेमेंट पर ऑफरः 5,000 रुपये का सीधा डिस्काउंट
- अंतिम कीमतः 55,000 रुपये
- अब आप नो कॉस्ट ईएमआई चुनते हैं डिस्काउंट घटकर 2,500 रुपये रह जाता है
- नई कीमतः 57,500 रुपये
- आपने शुरुआत में ही 2,500 रुपये ज्यादा दे दिए।
- अगर इसमें 499 प्रोसेसिंग फीस और उस पर 18% जीएसटी जोड़ दें, तो कुल खर्च लगभग 58,000 रुपये से ऊपर पहुंच सकता है।
- दिखने में ईएमआई आसान थी, लेकिन कुल भुगतान बढ़ चुका है।

सबसे बड़ा भ्रम हैः ईएमआई

- सुविधा=सस्ता सौदा
- असल में ईएमआई सिर्फ भुगतान को छोटे हिस्सों में बांटती है। खर्च कम नहीं करती।
- छोटी ईएमआई दिमाग पर दबाव कम डालती है। एकमुश्त 55,000 देने से ज्यादा आसान लगता है 4,800 रुपये की मासिक किस्त देना। लेकिन कुल रकम का हिसाब अक्सर नजरअंदाज हो जाता है।
- यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव है—छोटे नंबर कम डराते हैं।
- छिपे हुए चार्ज जिन पर कम ध्यान जाता है

ये अतिरिक्त खर्च संभव

- प्रोसेसिंग फीस : 199 से 999 रुपये या उससे अधिक
- जीएसटी : प्रोसेसिंग फीस या ब्याज वाले हिस्से पर 18%
- ईएमआई कन्वर्जन चार्ज

- लेट पेमेंट पेनल्टी (यदि किस्त समय पर न भरी जाए)
- ये सभी बातें अक्सर शर्तों में छिपी होती हैं, प्रोडक्ट पेज पर बड़े अक्षरों में नहीं लिखी होतीं।
- तुलनाः फुल पेमेंट बनाम नो कॉस्ट ईएमआई
- भुगतान तरीका दिखने वाली कीमत संभावित असली खर्च
- फुल पेमेंट 55,000 55,000
- नो कॉस्ट ईएमआई 57,500 58,000+

यह अंतर छोटा लग सकता है, लेकिन महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर या एसी जैसे उत्पादों में यह हजारों रुपये तक पहुंच सकता है।

कब नो कॉस्ट ईएमआई सही विकल्प

हर बार नो कॉस्ट ईएमआई गलत नहीं होती। कुछ परिस्थितियों में यह उपयोगी हो सकती है। आपके पास पूरी रकम उपलब्ध नहीं है। ईएमआई लेने से डिस्काउंट कम नहीं हो रहा। प्रोसेसिंग फीस शून्य है। आप कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए भुगतान फैलाना चाहते हैं। अगर इन शर्तों में से अधिकतर पूरी होती हैं, तो ईएमआई एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

निवेश के नजरिए से

व्यक्तिगत वित्त का एक मूल सिद्धांत है खर्च से पहले गणित करें। यदि आपके पास पर्याप्त बचत है और आप फुल पेमेंट कर सकते हैं, तो अक्सर वह सस्ता विकल्प होता है। ईएमआई चुनने से पहले यह सोचें।

सोचें क्या यह जरूरत है

- क्या ईएमआई के कारण मैं अतिरिक्त खर्च कर रहा हूं?
- क्या मैं कई ईएमआई का बोझ एक साथ उठा रहा हूं?
- कई बार लोग एक साथ 3-4 ईएमआई ले लेते हैं। छोटी-छोटी किस्तें मिलकर बड़ी मासिक देनदारी बन जाती हैं।

मार्केटिंग बनाम समझदारी

आज का ई-कॉमर्स माहौल भावनात्मक फैसले लेने को प्रेरित करता है। अभी खरीदें, बाद में भुगतान करें। लेकिन समझदार खरीदार पहले कैलकुलेशन करता है, फिर निर्णय लेता है। नो कॉस्ट ईएमआई धोखा नहीं है, लेकिन अधूरी जानकारी नुकसान में बदल सकती है। नो कॉस्ट ईएमआई सुविधा देती है, लेकिन हर सुविधा की एक कीमत होती है चाहे वह सीधी दिखे या छिपी हुई हो। इसलिए पहले पूरा गणित समझें, कुल भुगतान जोड़ें, और फिर फैसला लें। क्योंकि समझदारी से किया गया खर्च ही असली बचत है।